जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 87 प्रभात जालोर, शुक्रवार 4 जुलाई, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'अमेरिका, उन देशों पर जो रूस से ऑयल खरीदना जारी रखेंगे, 500 प्रतिशत टैरिफ लगायेगा'

अमेरिका के सिनेट में प्रस्तुत इस विधेयक, जिसे दोनों पार्टियों, रिपब्लिकन व डेमोक्रेटिक पार्टी, का आंशिक समर्थन प्राप्त है, का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

वॉशिंगटन/नई दिल्ली, 3 जुलाई। अमेरिकी सिनेट में पेश एक नया बिल (सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025, एस.1241) यह कहता है कि जो भी देश, जिनमें भारत भी शामिल है, से रूस से तेल, गैस, पैट्रोकेमिकल्स या यूरेनियम की खरीद जारी रखेंगे, उनके उत्पादों पर अमेरिका 500 प्रतिशत टैक्स (आयात शुल्क) लगा सकता है।

यह विधेयक सीनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल द्वारा पेश किया गया है और इसे 80 से अधिक सीनेटरों का समर्थन प्राप्त है। डॉनल्ड ट्रम्प ने न केवल इस विधेयक के कांग्रेस में पारित होने का समर्थन किया है, बल्कि भविष्य के राष्ट्रपतियों को रूस पर दबाव बनाने के लिए एक "टूलबॉक्स" देने की वकालत की है, हालांकि उन्होंने इसमें एक प्रेज़िडेंशियल छूट का प्रावधान भी सुनिश्चित किया है, जिससे राष्ट्रपति चाहें तो टैरिफ को निलंबित कर सकते हैं।

- रूस ने प्रत्युत्तर में चेताया है कि भारत जैसे देश पर इस तरह का दबाव बनाना, यूक्रेन में चल रहे शांति प्रयास को जोखिम में डाल सकता हैं।
- भारत, अमेरिका को फार्मास्युटिकल्स, टैक्सटाइल्स, आईटी सर्विसज़, ऑटो पार्ट्स तथा जवाहरात निर्यात करता है। भारत के ये निर्यात, अमेरिका में बिना किसी रूकावट के पहुँचते हैं। पर, अगर, अमेरिका ने भारत के इस निर्यात पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाया तो ये आईटम इतने महँगे हो जायेंगे कि अमेरिका में इनकी बिक्री खत्म सी हो जायेगी।
- अमेरिका अपनी इकोनॉमिक ताकत का उपयोग, भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने के लिए काम ले सकता है। अतः भारत ने अब ज्यादा से ज्यादा ऑयल अमेरिका से खरीदना शुरु कर दिया है, जिससे वो अमेरिका की व्यवसायिक धमकी में भी जी सके तथा अमेरिका के समृद्ध मार्केट में दीर्घकालीन एन्ट्री बनाये रख सके।

क्रेमलिन ने चेतावनी दी है कि भारत जैसे प्रमुख खरीदारों पर दबाव डालने जैसे कदम यूक्रेन में शांति प्रयासों को कमज़ोर कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह 500 प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव एक गंभीर खतरा है। यह उन देशों को निशाना बनाता है, जो रूस से तेल खरीद जारी रखते हैं, लेकिन यह दंड सीधे उनके तेल व्यापार पर लागू नहीं होता।

भारत के संदर्भ में, यद्यपि वह अपनी कुल जरुरत के कच्चे तेल 40 प्रतिशत आयात रूस से करता है, लेकिन अमेरिका को वह तेल निर्यात नहीं करता, इसलिए ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष टैरिफ लगाने का कोई रास्ता प्रत्यक्ष नहीं है। भारत को यह झटका किसी और क्षेत्र से लग सकता है, खासकर अन्य क्षेत्रों में अमेरिका को किये जाने वाले निर्यात से।

इन क्षेत्रों में फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, आईटी सेवाएं, ऑटो पार्ट्स और रत्न-आभूषण शामिल हैं, जो फिलहाल अमेरिका में न्यूनतम व्यापार बाधाओं के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी को मिला घाना का सर्वोच्च सम्मान

अक्कारा/नयी दिल्ली, 03 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को घाना के सर्वोच्च सम्मान, 'द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना' से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जॉन महामा ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया।

मोदी ने बुधवार को इस सम्मान के लिए घाना के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और इसे 'अत्यंत गर्व का विषय' बताया। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ भारतीयों की ओर से पुरस्कार स्वीकार करते हुए इस सम्मान को भारत के युवाओं की आकांक्षाओं, इसकी सांस्कृतिक परंपराओं और विविधता तथा घाना और

- घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने मोदी को '' ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना'' से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, इससे वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।

भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित किया। मोदी ने इस विशेष सम्मान के लिए घाना के लोगों और सरकार को धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार दोनों देशों के बीच मित्रता को और गहरा करता है तथा द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की उन पर नई जिम्मेदारी डालता है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि घाना की उनकी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार में मतदाता के धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति शुरु हो गई?

भाजपा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर ''नमाज़वादी'' होने का व्यंग्य दागा तथा विपक्ष ने भाजपा पर एनआरसी (नैशनल रजिस्टर फॉर सिटिज़न्स) को पीछे के दरवाजे से लाकर लागू करने का आरोप लगाया

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3, जुलाई। चुनाव की ओर बढ़ रहे बिहार में मतदाताओं का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण शुरू हो गया है। जहाँ भाजपा ने राजद (राष्ट्रीय जनता दल) नेता तेजस्वी यादव पर "नमाज़वादी" तंज कसते हुए इसकी शुरुआत की, वहीं विपक्षी नेताओं ने एनडीए पर एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश का आरोप लगाया है।

तेजस्वी यादव द्वारा यह कहे जाने पर कि वक्फ एक्ट को कचरे में फेंक दिया जाएगा और बिहार में लागू नहीं किया जाएगा, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने महागठबंधन के नेताओं पर शरिया कानून लागू करने की मंशा रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति "सभी जातियों और समुदायों के लिए काम" करने की रही है।

- तेजस्वी यादव का दावा है कि वक्फ एक्ट को कूड़े की टोकरी में फैंक दिया जायेगा तथा बिहार में कभी लागू नहीं होगा, पर, संबित पात्रा ने कहा कि महागठबंधन बिहार में "शरिया कानून" लागू करना चाहता है।
- प.बंगाल की मु.मंत्री ने कहा कि बिहार में स्पैशल इन्टैन्सिव रिवीज़न (एसआईआर) को लागू करने का असली टारगैट तो प.बंगाल है। बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं के नाम मिटा दिए जाएंगे तथा उनकी जगह, बिहार, यू.पी., राजस्थान, हरियाणा आदि के मतदाताओं से भर दी जायेगी।
- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मु.मंत्री नीतीश कुमार ने 2019 में बिहार में एनआरसी लागू करने के बारे में कहा था, "कहाँ का एनआरसी। बिल्कुल लागू नहीं होगा।" देखना है, अब उनका रुख क्या रहता है।

इस बीच, चुनाव आयोग द्वारा बिहार की मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव रिवीज़न-एसआईआर) कराने के निर्णय को लेकर एक बड़ा विवाद उभरता दिख रहा है। इस प्रक्रिया के तहत, 2003 के बाद मतदाता सूची में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाक हॉकी टीम को भारत में खेलने की अनुमति मिली

पाक टीम एशिया कप और एफआईएच जूनियर वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी, जो भारत में आयोजित हो रहे हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 3 जुलाई। पाकिस्तान की हॉकी टीम को अगले महीने भारत में होने वाले एशिया कप में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा, यह जानकारी खेल मंत्रालय के सूत्रों ने दी। यही नहीं मदुरै के होने वाले एफ.आई.एच. जूनियर वर्ल्ड कप अण्डर 21 में पाकिस्तानी टीम को खेलने की अनुमति मिली है। सूत्र ने कहा, "हम किसी भी टीम के भारत में हो रही बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन दो देशों के बीच सीरीज होना अलग मामला है।"

सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी टीमों को भारत आने की अनुमति विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है, और खिलाड़ियों के वीज़ा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार के एक उच्च-स्तरीय सूत्र ने बताया कि इस निर्णय की जानकारी मेज़बान संघ, हॉकी इंडिया, को दे दी गई है और उसने यह जानकारी अपने

- पाक टीम की वीज़ा प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है। सूत्रों ने कहा, भारत सरकार ने अगर पाक टीम को अनुमति नहीं दी होती तो ऑलम्पिक संघ से प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता था।
- ज्ञातव्य है कि अगले माह 27 अगस्त से 7 सितम्बर तक बिहार के राजगीर में एशिया कप हॉकी का आयोजन होगा और 28 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक मदुरै में जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामैंट का आयोजन होगा।
- भारत सरकार ने कहा कि यह अनुमति अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए दी गई है। द्विपक्षीय सीरीज़ का आयोजन एक अलग विषय है।

पाकिस्तानी समकक्ष को भी दे दी है। एक सूत्र ने कहा, "यह निर्णय भारत सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है जिसमें राजनीति और खेल को अलग रखने की बात कही गई है, साथ ही ओलंपिक चार्टर के सिद्धांतों का पालन किया गया है, जो भाग लेने वाले देशों के बीच राजनीतिक मतभेदों के बावजूद समावेश और सौहार्द की बात करता है।"

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भारत ने पाकिस्तान टीमों को भागीदारी से रोका होता, तो भारतीय ओलंपिक संघ को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक लाख करोड़ रु. से अधिक के रक्षा सौदे मंजूर

नयी दिल्ली, 03 जुलाई। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों तथा उपकरणों और रक्षा सम्बन्धी साजो-सामान से लैस करने के लिए एक लाख पांच हजार करोड़ रूपये के दस रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को यहां हुई रक्षा

- रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में यह भी फैसला हुआ कि यह खरीद स्वदेशी रक्षा उद्योग से की जाएगी।

खरीद परिषद की बैठक में, इससे संबंधित प्रस्तावों को आवश्यकता के आधार पर खरीद की मंजूरी दी गयी।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह खरीद (भारतीय-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) श्रेणी के तहत स्वदेशी रक्षा उद्योग से की जायेगी। इनमें सेना के लिए बख्तरबंद

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'एस.आई.आर. लागू हुआ तो बिहार के 20% मतदाता अपना ''वोटिंग'' का अधिकार खो देंगे'

इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग से कहा कि बिहार के ''माइग्रैंट वर्कर'' (घुमंतु मजदूर) 1 महीने में अपने आप को नये तरीके से मतदाता के रूप में ''रजिस्टर'' नहीं कर पायेंगे

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 3 जुलाई। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग द्वारा राज्य की मतदाता सूची की स्पेशल इन्टैन्सिव रिव्यू (एस. आई. आर.) कराने के फैसले से बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं में से 20 प्रतिशत लोग निर्वाचनाधिकार से वंचित हो जाएंगे।

बुधवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ विपक्षी गठबंधन की बैठक के दौरान तीखी नोकझोंक की खबरें सामने आई हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने एस. आई. आर.) के खिलाफ कानूनी दलीलें पेश कीं, ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व और अलोकतांत्रिक कदम है कि आयोग ने केवल राजनीतिक दलों के अध्यक्षों या उनके द्वारा नामित नेताओं से ही मिलने का निर्णय लिया। सिंघवी ने कहा

- चुनाव आयोग ने एस.आई.आर. लागू करने के लिए तर्क दिया कि महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में विपक्ष के नेताओं ने स्वयम् कई प्रश्न उठाये थे, मतदाता सूची के बारे में।
- कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्टी का पक्ष रखा और कहा, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, जैसे, जयराम रमेश, पवन खेड़ा तथा बिहार के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, चुनाव आयोग के साथ मीटिंग में भाग नहीं ले पाये और तीन घंटे बाहर ही बैठे रहे। क्योंकि, अचानक निर्वाचन सदन ने निर्णय लिया कि केवल पार्टी द्वारा मनोनीत एक नेता ही चुनाव आयुक्त से मिल सकेगा।

कि जब विभिन्न दलों के 20 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन सदन पहुँचा, तो उन्हें बताया गया कि केवल पार्टी प्रमुखों को ही अंदर जाने की अनुमति है। इसके चलते, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह बैठक में शामिल नहीं हो सके और उन्हें लगभग तीन घंटे तक बाहर इंतजार करना पड़ा।

राजद सांसद मनोज कुमार झा और सीपीआई (माले) के नेता दीपंकर भट्टाचार्य भी सिंघवी के साथ बैठक में मौजूद थे। भट्टाचार्य ने एस. आई. आर. की तुलना "वोटबंदी" से की, यह कहते हुए कि बिहार के प्रवासी मजदूर चुनाव आयोग द्वारा तय की गई एक महीने की समयसीमा में दोबारा नामांकन नहीं करवा पाएंगे। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए चुनाव चुराने की कोशिश का आरोप लगाया और कहा कि महागठबंधन के वोटरों को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है।

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने एस. आई. आर. की आवश्यकता को उचित ठहराते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं ने ही पिछले साल महाराष्ट्र चुनाव के बाद मतदाता सूची पर कई सवाल उठाए थे।

सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग ने उनकी बातें सुनीं, लेकिन उन्हें स्वीकार करने में रुचि नहीं दिखाई, वहीं, झा और भट्टाचार्य सहित कई विपक्षी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि एस. आई. आर. की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, तो वे जन आंदोलन शुरू करेंगे।

रिश्वत प्रकरण में बागीदौरा विधायक के खिलाफ चालान पेश

जयपुर, 3 जुलाई। एसीबी ने विधानसभा में लगाए गए प्रश्नों को वापस लेने के लिए रिश्वत मांगने के मामले में बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल सहित, चार आरोपियों के खिलाफ एसीबी मामलों की विशेष कोर्ट में चालान पेश कर दिया। एसीबी ने चालान में एमएलए पर लोक सेवक होते हुए भी

- एसीबी ने विधायक जयकृष्ण पटेल के साथ उनके चचरे भाई विजय कुमार पटेल, लक्ष्मण सिंह मीणा तथा जगराम मीणा को भी आरोपी बनाया है।

पद का दुरुपयोग करने और उसका अनुचित लाभ लेने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित बीएनएस की धाराओं में आरोप लगाए हैं। इसके अलावा, आरोप पत्र में एमएलए के चचेरे भाई विजय कुमार पटेल, लक्ष्मण सिंह मीणा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेसाध्यक्ष खड़गे ने प्र.मंत्री मोदी पर तीन प्रश्न दागे, अपने ट्विटर हैण्डल से

खड़गे के सवालों का आशय है कि चीन बार-बार भारत के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है, पर, भारत फिर भी चीन की तरफ ही देख रहा है

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 3 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक नए और प्रभावशाली तरीके से घेरते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज तीन सुर्खियों और तीन सवालों के ज़रिए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने फ़ॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप द्वारा सैकड़ों चीनी इंजीनियरों और तकनीशियनों को भारत के आईफोन संयंत्रों से वापस बुलाए जाने की खबर को अपने हमले का मुद्दा बनाया।

खड़गे ने फ़ॉक्सकॉन की इस कार्रवाई को रेखांकित किया, जिसे भारत में एप्पल के उत्पादन विस्तार के प्रयासों को झटका माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि 300 से अधिक चीनी कर्मचारी भारत के संयंत्रों से वापस जा चुके हैं।

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा "मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन ने भारत के विनिर्माण क्षेत्र से अपने अधिकारियों को वापस बुला लिया है।"

इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाया "क्या यह सच नहीं है कि मोदी सरकार, जो मेक

- खड़गे ने पहला उदाहरण दिया, फॉक्सकान कंपनी ने भारत में लगे प्लांट से 300 चीनी वर्कर व इंज़िनियरों को वापस चीन बुला लिया, जिससे एपल कंपनी के भारत को अपना नया मोबाइल फोन बनाने का "हब" बनाने के प्रोग्राम को भारी धक्का लगा।
- इसी प्रकार चीन ने ऑटोमोबाइल, ईवी, डिफैंस व हाई सिक्युरिटी प्रिंटिंग मशीनों में काम आने वाले रेअर अर्थ मैगनेट व मिनरल्स का भारत को निर्यात एकदम बंद कर दिया है। चीन इस मुद्दे पर भारत से बात करने के लिए भी राजी नहीं है तथा भारत की ऑटोमोबाइल इण्डस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय भी नहीं दिया है।
- इसके अलावा चीन ने भारत को स्पैशिएलिटी फर्टिलाइज़र का निर्यात भी बंद कर दिया है, जबकि चीन यह फर्टिलाइज़र अन्य देशों को खुलकर निर्यात कर रहा है। यह विशेष फर्टिलाइज़र फल, सब्जी तथा अन्य विशेष कृषि उत्पादों में उपयोग में आता है तथा इसके उपयोग से किसान को अच्छा लाभ होता है।

इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में पूरी तरह से असफल रही है, उसने डोकलाम और गलवान को भुला दिया और चीनी कंपनियों के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछा दिया? साथ ही, पी एल आई स्कीम का लाभ उठाने के लिए चीनी नागरिकों को वीज़ा जारी करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया?"

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव-पी एल आई) योजनाएं सरकार की ऐसी पहलें हैं, जिनका उद्देश्य भारत में निर्माण को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ाना और विदेशी निवेश आकर्षित करना है।

चीन द्वारा भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति रोकने की खबरों पर खड़गे ने लिखा: "चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स और मिनरल्स का निर्यात सख्ती से रोक दिया है, जो अन्य क्षेत्रों के अलावा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन रक्षा, और हाई-सिक्योरिटी करंसी प्रिंटिंग जैसे क्षेत्रों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। क्या यह सच नहीं है कि मोदी सरकार इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रही है, और भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के प्रतिनिधिमंडल को चीनी अधिकारियों से मुलाकात की अनुमति तक नहीं मिली है?"

खड़गे ने विशेष उर्वरकों (स्पेशएलिटी फर्टीलाइज़र्स) की आपूर्ति रोकने को लेकर भी सरकार पर हमला बोला: "पिछले दो महीनों में चीन ने भारत को विशेष उर्वरकों का निर्यात बंद कर दिया है, जबकि अन्य देशों को इनकी सप्लाई जारी है। भारत 80 विशेष उर्वरक चीन से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आसाराम की जमानत अवधि एक माह और बढ़ी

अहमदाबाद, 03 जुलाई। गुजरात हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम की अस्थायी जमानत एक और महीने के लिए बढ़ा दी है, लेकिन साफ कहा है कि यह आखिरी विस्तार होगा। 86 वर्षीय आसाराम को 2013 के एक दुष्कर्म केस में उम्रकैद की सजा

- गुजरात हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए यह कहा कि यह आखिरी विस्तार है, इसके बाद जमानत अवधि नहीं बढ़ेगी।

मिली है और वे चिकित्सकीय आधार पर जमानत पर हैं।

गुरुवार को न्यायमूर्ति ईलेश वोरा और पीएम रावल की पीठ ने उनकी जमानत में एक महीने की और मोहलत दी। इससे पहले, कोर्ट ने 28 मार्च को उन्हें अस्थायी जमानत दी थी, जो 30 जून को समाप्त हो रही थी। कोर्ट ने पहले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)